भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3171

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुलों की स्थापना

3171. श्री विजय बघेलः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुलों (ईएमसी) की कुल संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार की छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुल स्थापित करने की कोई योजना है क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं; और

(ग) क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य में संकुल के लिए किसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना, लॉजिस्टिक और प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करने के लिए, एमईआईटीवाई ने 1 अप्रैल 2020 को संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना और 2012 में ईएमसी योजना शुरू की।

ईएमसी योजनाओं के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में 2 परियोजनाओं सहित 18 राज्यों में कुल 30 ईएमसी परियोजनाओं और 5 सीएफसी को स्वीकृति दी गई है।

नया रायपुर के सेक्टर-22 में 103.88 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक ग्रीनफील्ड ईएमसी को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 116.48 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली 43.08 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

56 एकड़ के बिक्री योग्य क्षेत्र में से 41.78 एकड़ आवंटित किया गया है, और नौ (09) विनिर्माण कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, अटल नगर, रायपुर में 108.43 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 3.23 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाली 75 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

सीएफसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को सहयोग देने के लिए डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण और माप के लिए साझा सुविधाएं प्रदान करता है। सीएफसी के अंतर्गत अनुमानित निवेश 70 करोड़ रुपये और 2,500 नौकरियों के रोजगार सृजन का अनुमान है।

******